«

13. डा . ए. के . बसु ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसाइटी बरियात् रांची (बिहार) - 894009	सदस्य
14. श्री अलोसियस पी . फनर्डिज सदस्य कार्यकारी निदेशक मैसूर रिसेटैलमेंट एंड ड्वेलपमैंट एजेंसी 2 सर्विस रोड हमलूर बैंगलोर -562071	सदस्य
15. प्रो . वी. एस. व्यास निर्देशक इंस्टीट्यूट ऑफ डवैलपमैंट स्टडीत 8- बी मौलान इंस्ट्च्यूशनल एरिया जयपुर -302004	सदस्य
16. अध्यक्ष खादी ग्रामोदयोग आयोग इर्ला रोड बिले पारले (वेस्ट) बम्बई -400056	सदस्य
17. श्री जे. एम. चोना आर्थिक सलाहाकार सरल प्लार्गि एंड क्रेडिट विभाग रिर्जव बैंक आफफ इंडिया बम्बई	सदस्य सचिव

* अब सेवा निवृत हो चुके हैं।

श्री के , कैनन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, देना बैंक को श्री भागवत के स्थान पर नियुक्त किया गया ।

भारतीय रिजर्व बैंक से सेवा निवृत हो चुके हैं। श्री के. के मुदगिल, मुख्य अधिकारी ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग , केन्द्रीय कार्यालय ,भारतीय रिजर्व बैंक 25.07.1994. से सदस्य सचिव नियुक्त हुए हैं।

Tussle between Director and President of AIIMS

502. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there was tussle between the Director and. President of the All India Institute of Medical Science (AIIMS), Delhi; and

(b) if so, what steps have been taken to avoid general deterioration, frustration and demoralisation in all ranks of the faculty?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rate of interest on loans of Kbadi and Village Industries

503. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state whether Government propose to reconsider its decision to enhance the rate of interest of the loans of the Khadi and Village Industries Boards and Khadi commission,-from 4% to a higher rate so as to help the poor applicant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): On the basis of the recommendations of the High Power Committee, the scheme of providing interest subsidy on loans for the village industries has been discontinued. In its recommendations, the Committee has emphasised the need to obtain adequate finance rather than concessional finance for village industries.

As a follow up on the re-commendations of the Committee, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) has been permitted to provide margin money upto 25% of the project cost subject to a ceiling of Rs. 4 lakhs n the form of grant for all viable village

industry projects. In order to improve availability of credits of Khadi & Village Industry (KVI) sector, the Government have also given gurantee in favour of the KVIC so that they could avail of loans upto Rs. 1000 crores from a consortium of banks for further lending to viable KVI projects. This has been done in accordance with the announcement made by the Finance Minister in his budget speech for the year 1995-96 as part of the measures for improving availability of bank credit for the KVI sector.

Exodus of Senior Doctors from AIIMS

504. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the exodus of senior doctors from the AIIMS continuous unabated;

(b) if so, what is the number of senior doctors who left the AIIMS during the last six months;

(c) whether a Committee of senior doctors was set up to identify the causes for the exodus of AIIMS doctors; and

(d) if so, what are the findings of the Committee and what action has been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (d) Some doctors at middle level have left AIIMS for alternative jobs. A Committee of Senior doctors has been formed by the Director and its report will be placed before the Governing Body of the Institute.

छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

505. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार को इस संबंध में विभिन्न सामजिक संगठनों और वकीलों से अब तक पिछले कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या छत्तीसगढ़ में न्यायपीठ के संबंध में रायपुर के दावे पर विचार किया जा रहा हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (घ) विभिन्न स्थानों पर, जिनके अन्तर्गत मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रायपुर भी हैं, उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों और व्यष्टिकों से समय-समय पर आभ्यावेदन प्राप्त होते रहें हैं। आभ्यावेदनों की संख्या बताना संभव नहीं हैं। इस विषय को 1983 में जसवंत सिंह आयोग को निर्दिष्ट किया गया था आयोग ने अप्रैल , 1985 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में रायपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने की सिफारिश की हैं।

जसवंत सिंह आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अक्तूबर ,1986 में मध्य प्रदेश सरकार को विचार और टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया था। राज्य पुनगर्ठन अधिनियम , 1956 की धारा 51 (2) के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

अतः यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

Manufacture of Main Battle Tank

506. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the status of development and manufacture of the Main Battle Tank; and

(b) whether any shortcomings are still to be removed and improvements arc considered necessary?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND